गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 157
दि. 06.10.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

कफ सिरप विवाद पर केंद्र सरकार का सख्त रुख नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस रद्द करने का संकेत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बच्चों के लिए निर्मित कफ सिरप की गुणवत्ता और इसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि दवा निर्माता कंपनियों को संशोधित Schedule M के तहत गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनदेखी या मानकहीन उत्पादन पाए जाने पर कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों में खांसी सामान्य होती है और अक्सर यह खुद-ब-खुद ठीक हो जाती है। "बिना आवश्यकता के कफ सिरप देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अभिभावक सोच-समझकर ही दवा दें और हल्की खांसी में घरेलू उपाय अपनाएं," उन्होंने कहा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अस्पतालों से दवा संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट समय पर मंगाई जाए और सभी रिपोर्टें IDSP-IHIP (Integrated Disease Surveillance Programme – Integrated Health Information Platform) पर दर्ज हों। राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए ताकि संदिग्ध मामलों पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में बच्चों की मौत और गंभीर बीमारियों से जुड़े कफ सिरप मामलों ने इस कदम को जरूरी बना दिया। इन मामलों में दवा में विषैले रसायन या मानक से कम गुणवत्ता पाए जाने के कारण भारत की फार्मास्युटिकल छवि को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हुआ।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता है और भारतीय दवाओं का निर्यात कई देशों में होता है। हाल के विवादों ने इस वैश्विक छवि को प्रभावित किया है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब बच्चों की दवाओं पर किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Schedule M भारतीय दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का वह हिस्सा है जो निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों के लिए दिशा-निर्देश देता है। संशोधन के बाद इसे और कठोर बनाया गया है, जिसका पालन सभी दवा कंपनियों के लिए अनिवार्य है।

केंद्र सरकार का यह कड़ा रुख बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे निगरानी और कार्रवाई के स्तर को और मजबूत करें। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दें। हल्की खांसी में घरेलू उपाय और सतर्क निगरानी ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

इस निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि दवा कंपनियां गुणवत्ता में ढिलाई नहीं बरतेंगी और भविष्य में इस प्रकार के घातक विवादों को रोका जा सकेगा।

चीनी सहकारी मिलों की बदलती तस्वीर, अमित शाह ने किसानों को राहत का भरोसा दिलाया

(जीएनएस)। अहमदनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदनगर जिले के डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की क्षमता विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के चीनी सहकारी क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और महाराष्ट्र में सहकारी मिलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से लगभग 60 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है और केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए तुरंत कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने राहत कार्यों में तेजी लाने का दावा किया। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 3132 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है, जिसमें से 1631 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अप्रैल में जारी किए गए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2215 करोड़ रुपये का राहत कोष बनाया है, जिससे 31 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। महाराष्ट्र सरकार किसानों को 10 हजार रुपये नकद और 35 किलो अनाज भी मुहैया करा रही है, साथ ही कर्जमाफी की वसूली पर रोक भी लगाई गई है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य के विधायकों ने एक महीने का वेतन राहत कोष में दान किया है और राधाकृष्ण विखे पाटिल की फैक्ट्री को भी सहायता दी जाएगी। कई ट्रस्टों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आगे आकर राहत कार्यों में योगदान दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि यह सब तभी संभव हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार को चुना है। उन्होंने किसानों से भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से उपजी स्थिति को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने राहत कार्यों में तेजी लाने और किसानों को हर संभव आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देने का पूर्ण संकल्प जताया है।

बरेली हिंसा की जांच के लिए AAP का प्रतिनिधिमंडल 7 अक्टूबर को बरेली में पहुंचेगा

(जीएनएस)। बरेली। 26 सितंबर को बरेली में 'I Love Muhammad' को लेकर हुए विवाद और उसके बाद फैली सांप्रदायिक अशांति ने राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बरेली भेजने का निर्णय लिया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को इस दौरे की घोषणा की। संजय सिंह ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल 7 अक्टूबर को बरेली का दौरा करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विवाद की निष्पक्ष जांच, पीड़ितों से संवाद स्थापित करना और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ₹सरकार पीड़ितों की आवाज़ को दबा रही है, इसलिए AAP का कर्तव्य है कि वह सच सामने लाए।₹

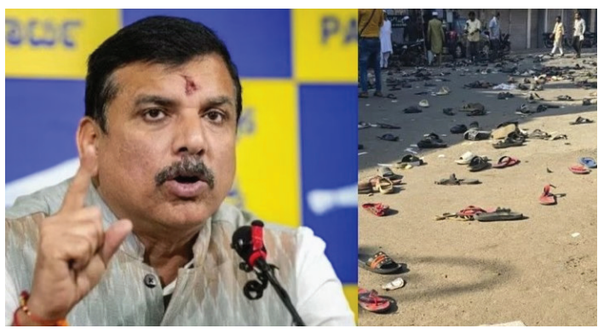

प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिनमें प्रदेश सह प्रभारी दिलीप पांडेय, पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका, रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष मो. हैदर, बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ, महिला विंग अध्यक्ष नीलम यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. छवि यादव, यूथ विंग अध्यक्ष पंकज अवाना, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमांडो अशोक, प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला, बरेली जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्या और पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय सिंह शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रांत प्रभारी और पदाधिकारी भी इस दौरे में सम्मिलित होंगे।

संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली की घटना एक सोची-समझी साजिश है, ताकि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो बिना वैधानिक प्रक्रिया के बुलडोज़र चलवाने वाले अफसरों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है।

AAP के इस दौरे से पहले समाजवादी पार्टी भी 4 अक्टूबर को 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बरेली जाने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। अब यह देखने की बात होगी कि AAP प्रतिनिधिमंडल को प्रशासनिक अनुमति मिलेगी या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि AAP का यह दौरा उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी और जनाधार मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। बरेली की घटना ने सभी सियासी दलों को एकजुट होने का अवसर दिया है और यह दौरा आगामी चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है।

'10 साल का ब्राह्मण, 100 क्षत्रिय का पिता': स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बोला हमला

(जीएनएस)। अमेठी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी (एजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को अमेठी में आयोजित जनसभा के दौरान विवादास्पद बयान देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। मंच से मौर्य ने कहा, "संस्कृत में लिखा है कि 10 साल का ब्राह्मण, 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है।" इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने सभा में एक श्लोक का हवाला देते हुए ब्राह्मणों को उच्चतर बताते हुए कहा कि यह जातीय असमानता का प्रतीक है और अब समय आ गया है कि इस मानसिकता को चुनौती दी जाए।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हुए हमले जैसी घटनाएं प्रदेश में जंगलराज की स्थिति दिखाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 'हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद' जैसे भावनात्मक मुद्दों को जनता का ध्यान भटकाने के लिए बार-बार उठाती है, जबकि आम जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

मौर्य ने अपनी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए किसी दल के साथ गठबंधन करना पड़ा तो वे इसके लिए तैयार हैं। मौर्य ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि देश भारतीय संविधान के नियमों से चलेगा, किसी ढोंगी बाबा के कहने से नहीं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश को आज़ाद कराने में सभी धर्मों और जातियों ने योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग धर्म का चोला पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। वह पांच बार विधायक, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2022 में उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामा और फाजिलनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सपा भी छोड़ दी और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (आरएसएसपी) की स्थापना की। हाल ही में उन्होंने अपनी जनता पार्टी (एजेपी) का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह कुशीनगर से आरएसएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे।

गाज़ा पर नियंत्रण नहीं छोड़ा तो होगा पूर्ण विनाश: ट्रंप ने हमास को दी अंतिम चेतावनी

(जीएनएस)। वॉशिंगटन/गाज़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को हमास को अंतिम चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर संगठन गाज़ा की सत्ता और नियंत्रण नहीं छोड़ता और उनकी शांति योजना स्वीकार नहीं करता, तो उसे पूरी तरह विनाश का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव स्वीकार करने, इज़रायली बंधकों को रिहा करने और लड़ाई बंद करने के लिए सोमवार सुबह 03:30 बजे तक की समय-सीमा दी थी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह उनका आखिरी मौका है। यदि हमास योजना मान लेता है, तो युद्ध तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ट्रंप की युद्धविराम योजना का समर्थन कर चुके हैं। ट्रंप की ओर से पेश की गई 20-बिंदु शांति योजना में गाज़ा की भविष्य की व्यवस्था की रूपरेखा भी शामिल है। योजना के मुख्य बिंदु में गाज़ा में तत्काल युद्धविराम, अस्थायी प्रशासनिक बोर्ड का गठन जिसमें अंतरराष्ट्रीय हस्तियां और ट्रंप का प्रतिनिधित्व शामिल होगा, और नागरिकों को उनके घरों से बेदखल न करने का आश्वासन शामिल है। यदि दोनों पक्ष शर्तें मानते हैं, तो लड़ाई तत्काल रुकेगी। हमास ने योजना के कुछ हिस्सों जैसे युद्ध समाप्त करना, इज़रायली

सेनाओं की वापसी और बंधकों की रिहाई का समर्थन किया है, लेकिन हथियार छोड़ने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संगठन अभी भी बातचीत करना चाहता है। इस विषय पर मिस्र में हमास, इज़राइल और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं ने चेतावनी दी है कि गाज़ा में युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि बंधकों की रिहाई पहला कदम होगा, उसके बाद ही गाज़ा के भविष्य और शासन व्यवस्था पर विस्तृत बातचीत संभव होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी बात की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती और कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की शांति पहल दोनों पक्षों के बीच समझौते पर निर्भर है। यदि हमास निर्धारित समय में शर्तें स्वीकार नहीं करता, तो क्षेत्रीय तनाव और मानवीय संकट और बढ़ सकते हैं, जिससे सैन्य टकराव की संभावना भी बढ़ जाएगी।

उत्तर बंगाल में बारिश और बाढ़ से तबाही, सेना और NDRF ने संभाला मोर्चा

(जीएनएस)। कोलकाता/दार्जिलिंग। उत्तर बंगाल इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। भारी वर्षा के कारण दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और डूआर्स क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें टूटने और पुल बह जाने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है और कई गांव बाहरी संपर्क से कट चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना, NDRF और राज्य पुलिस ने राहत और बचाव के मोर्चे संभाल लिए हैं।

सेना ने अस्थायी पुल निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर दुदिया में एक टीम तैनात की गई है, जो क्षेत्र में अस्थायी पुल बनाने का कार्य करेगी। सेना के इंजीनियरिंग कोर के अधिकारी हालात का जायजा लेकर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेंगे ताकि संपर्कविहीन इलाकों को जोड़ा जा सके।

भूटान के ताला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से उत्पन्न खतरा भी उत्तर बंगाल के लिए गंभीर है। बांध के गेट खुलने में तकनीकी दिक्कत के कारण पानी बांध के ऊपर फैल गया है। भूटान सरकार ने पश्चिम बंगाल को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यदि भारी बारिश जारी रही, तो नदियों में अचानक बाढ़ की आशंका बनी हुई है। एनडीआरएफ ने अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, मालदा और कोलकाता से टीमें तैनात कर हाई अलर्ट मोड घोषित कर दिया है। छुट्टी पर गए कर्मियों को वापस बुला लिया गया है और सिलीगुड़ी से अतिरिक्त 15 बचावकर्मियों को डूआर्स क्षेत्र भेजा गया है।

दार्जिलिंग उपखंड के मिरिक क्षेत्र में भूस्खलन से कई गांव प्रभावित हुए हैं और सड़क मार्ग बंद होने के कारण राहत सामग्री पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के साथ मिलकर रास्ते बहाल करने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात पर चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकार राहत कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों को हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से उठा तूफान डूआर्स क्षेत्र की ओर बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिससे अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहने की संभावना है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार में सेना और NDRF की टीमें सक्रिय हैं और प्रशासन ने नदी किनारे और ढलानों पर बसे गांवों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांध और नदियों के जलस्तर की निगरानी लगातार जारी है। राहत एजेंसियां युद्धस्तर पर काम कर रही हैं और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर बंगाल इस समय प्राकृतिक आपदा की चपेट में है और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।

पाकिस्तान रक्षा मंत्री की भारत पर युद्ध की धमकी, बोले- 'इंशाअल्लाह, विमानों के मलबे में दब जाएगा'

(जीएनएस)। नई दिल्ली/इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को एक उग्र बयान देते हुए भारत को युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने भविष्य में कोई दुस्साहस किया, तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। उनका यह बयान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हालिया सख्त चेतावनियों के जवाब में आया।

आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ₹भारत सरकार घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तनाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना देश है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार इंशाअल्लाह, भारत अपने विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। अल्लाहु अकबर।₹ उनका यह बयान न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय भी बन गया है।

इससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' का विवरण साझा करते हुए बताया था कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, भारतीय वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट्स और सर्विलांस विमानों सहित पाकिस्तान के कई सैन्य उपकरणों को ध्वस्त किया। तीन एयरबेस के हैंगरों पर हमले में 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तबाह हुए। सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमान 300 किमी तक पाकिस्तान में घुसकर सटीक हमले करने में सफल रहे। ख्वाजा आसिफ ने अपने पोस्ट में भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत अपनी '0-6 की हार' की बदनामी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ₹0-6₹ किस सन्दर्भ में कहा गया है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, यह पाकिस्तान की मनगढ़ंत बयानबाजी का हिस्सा प्रतीत होती है, क्योंकि हाल के किसी भी संघर्ष में भारत को ऐसी कोई पराजय नहीं मिली है।

भारत सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है और ऐसे समय में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है।

संपादकीय

आधारभूत सुविधाओं की कमी से फल—फूल रहे हैं पाखंडी धर्म गुरु

भारत में आधारभूत सुविधाओं की कमी एक जटिल मुद्दा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और शहरी क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे (जैसे सड़कें, पुल, आदि) में खामियाँ पाई जाती हैं। इसके मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में बाधाएँ, भ्रष्टाचार, कुशल प्रबंधन की कमी और मांग में वृद्धि हैं। ऐसे हालात देश में ढोंगी बाबाओं को पनपने का मौका देते हैं। ऐसे फर्जी बाबाओं, मौलवियों और पादरियों की सूची में एक नाम और जुड़ गया है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट में यौन शोषण के मामला मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 17 छात्राओं ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को देर रात कथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के क्वार्टर में बुलाया जाता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और उस पर पहले भी 2009 और 2016 में छेड़छाड़ के केस दर्ज हो चुके हैं। धर्म की आड़ लेकर ऐसे फर्जी बाबा, मौलवी और पादरियों की फेहरिस्त काफी लंबी हैं, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को शोषण किया बल्कि धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। देश में कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने धर्म की आड़ में लोगों का शोषण किया। बाद में पकड़े गए और अब जेल की सलाखों के पीछे हैं या फरार हैं। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा मिली। गुरमीत को बार-बार पैरोल और फरलो मिलने की वजह से विवाद भी रहा है। हाल ही में, अगस्त 2025 में उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई, जो उनकी 14वीं रिहाई थी।

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर सूरत की दो सगी बहनों से दुराचार, गवाहों पर हमला और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी सूरत की जेल में दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। हरियाणा के ही एक और बाबा संत रामपाल हिसार जेल में बंद हैं। सतलोक आश्रम चलाने वाले रामपाल पर देशद्रोह, शारीरिक शोषण, अवैध हथियार रखने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। स्वामी भीमानंद, जिन्हें इच्छाधारी बाबा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में देह व्यापार का रैकेट चलाने के आरोप में जेल में हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली आश्रम चलाने वाले स्वामी परमानंद भी जेल में बंद हैं। उनके ऊपर 13 महिलाओं से रेप के आरोप हैं।

सन 90 के दौर में धीरेंद्र ब्रह्मचारी के ऊपर अपनी गन फैक्ट्री में अवैध विदेशी हथियार रखने के आरोप लगे। एक तांत्रिक के रूप में विख्यात चन्द्रास्वामी के पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव से गहरे संबंध थे। ईडी ने उनपर 13 मामलों में फेमा के उल्लंघन के मामले में 9 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। लंदन के एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1996 में चंद्रास्वामी को गिरफ्तार किया गया था। राजीव गांधी हत्या मामले में भी उनपर हत्यारों की वित्तीय मदद करने के आरोप लगे थे। राजस्थान के अलवर जिले में बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबाफलाहारी बाबा यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा हुई। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुंबई में राधे मां विवादों में रही। उन पर मिनी स्कर्ट पहनने, भक्तों के गले लगना, उनके साथ डांस करना, यही वजह है कि उनपर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लग चुका है। स्वामी नित्यानंद दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए जिसके बाद उनके समर्थकों ने खासा हंगामा किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमालुद्दीन उर्फ़ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ़्तार भी किया। बलरामपुर जिले में उनके घर को बुलडोज़र से गिरा दिया। छांगुर बाबा पर धर्मांतरण, विदेशी फंड़िंग जैसे आरोप हैं। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी की। बरेली की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने मस्जिद की साफ सफाई करने वाली लड़की को जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ गलत काम किया।

स्वदेशी एवं स्वावलम्बन ही नये भारत का आधार

> संघ की स्थापना का यह अवसर केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। भागवत ने स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना महोत्सव यानी प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्बोधन एक नए संदेश और नये दृष्टिकोण के साथ सामने आता है, इस उद्बोधन का पूरा राष्ट्र इंतजार करता है। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें कहीं, जो सरकार के साथ समाज के लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए टैरिफ की चर्चा की। 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ ने भारत के समक्ष जो कठिन चुनौती खड़ी कर दी है, उसका प्रभावी ढंग से सामना स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही किया जा सकता है। भागवत ने संबोधन में स्वदेशी और स्वावलंबन को नए भारत का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में परस्पर निर्भरता एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यह निर्भरता कभी भी बंधन या मजबूरी में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि विदेशी निर्णयों और नीतियों पर हमारी नियंत्रण क्षमता सीमित न हो जाए। उनका कहना था कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी शर्तों पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंध बनाएं। संघ की स्थापना का यह अवसर केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। भागवत ने स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया। यह आयोजन संघ के सौ वर्ष सम्पूर्णता की साधना का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि आने वाले सौ वर्षों की दिशा का भी उद्घोष था। नई इबारत लिखते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की कार्यप्रणाली का सार है, नए मनुष्य एवं सशक्त-स्वावलम्बी भारत का निर्माण। यह

विचार सुनने में सरल लग सकता है, किंतु इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। समाज और राष्ट्र की सारी समस्याओं का मूल व्यक्ति के भीतर छिपा है। इसीलिये देश के सभी वर्गों को एकसूत्र में जोड़ने के संकल्प के साथ संघ आगे बढ़ेगा क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र, दृष्टि और आचरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती। संघ व्यक्ति-निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को बदलने की दीर्घकालिक साधना कर रहा है। यही कारण है कि संघ के कार्य का परिणाम केवल शाखाओं या कार्यक्रमों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि उस अदृश्य लेकिन ठोस नैतिक शक्ति एवं सशक्त राष्ट्रीय भावना में देखा जा सकता है, जो धीरे-धीरे समाज की दिशा बदल रही है। भागवत ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने विविधता को भारत की विशेषता बताया और समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर चेताया। उन्होंने पंच परिवर्तन की संकल्पना भी प्रस्तुत की जिसमें आत्मजागरूकता, पारिवारिक मूल्य, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को जोड़ा गया है। इस संदेश के सकारात्मक पक्ष अनेक हैं। यदि इसे गंभीरता से अपनाया जाए तो यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है। स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प और कृषि को बढ़ावा देने से रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक आत्मसम्मान मजबूत होगा। स्वदेशी पर बल देने से विदेशी निर्भरता घटेगी और देश की सुरक्षा व नीति संबंधी स्वतंत्रता बढ़ेगी। यदि समाज के स्तर पर भी इस सोच को अपनाया जाए तो उपभोक्तावाद के स्थान पर संवेदनशीलता और सेवा भाव विकसित होगा। विविधता के सम्मान और सामाजिक सद्भाव के आग्रह से राष्ट्र अधिक एकजुट और शक्तिशाली बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह संदेश देश की घरेलू क्षमताओं को सशक्त बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विकास की दिशा को व्यापक सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ता है, जिसमें महात्मा गांधी की 'स्वदेशी अपनाओ' और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 'अंत्योदय' की परिकल्पना स्पष्ट तौर पर समाहित है। स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही नया भारत-सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। इस बात को सरकार भी रेखांकित कर चुकी है और अब संघ प्रमुख ने भी दोहरा दिया। यह समय की मांग है कि स्वदेशी और स्वावलंबन पर तब तक बल दिया जाए, जब तक वांछित सफलता न मिल जाए। जहां सरकार को स्वदेशी की राह को आसान करना होगा, वहीं समाज को सहयोग देने के लिए तत्पर रहना होगा। इस उम्मीद में नहीं रहा जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ शीघ्र ही आपसी व्यापार समझौता हो जाएगा। एक तो जब तक ऐसा हो न जाए तब तक चैन से नहीं बैठा जा सकता और दूसरे, यदि ऐसा हो जाए तो भी भारत को स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलना छोड़ना नहीं चाहिए। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता लाचारी में नहीं बदलनी चाहिए। वास्तव में इस स्थिति से बचने का ही उपाय है स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। परंतु इस संदेश के साथ कई चुनौतियां और सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी आपस में गुँथी हुई है कि किसी भी देश का पूर्ण स्वावलंबन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अनेक तकनीकें और कच्चे माल अब भी हमें विदेशों से ही प्राप्त करने होते हैं। यदि स्वदेशी को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध या अधिक शुल्क लगाए जाते हैं तो यह व्यापार युद्ध और आर्थिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस संदेश की सफलता केवल भाषणों और भावनात्मक नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि ठोस नीतियों, बजट, शोध और योजनाओं के आधार पर इसे अमल में लाना होगा। सामाजिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा केवल एक सांस्कृतिक या राजनीतिक रंग में न ढल जाए। यह तभी कारगर होगा जब इसे हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र का साझा लक्ष्य बनाया जाएगा। नागरिकों की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन यदि यह बदलाव शिक्षा, प्रोत्साहन और जनचेतना के माध्यम से लाया जाए तो यह नारा समाज में गहरी जड़ें जमा सकता है। संघ प्रमुख का यह संदेश नए भारत की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति पर गर्व करना चाहिए, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से सशक्त होना चाहिए और विश्व के साथ संवाद स्थापित करते हुए भी अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए। किंतु इसके लिए आलोचनात्मक विवेक, व्यावहारिक सोच और निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। आज विभिन्न देशों की परस्पर मित्रता का आधार अपने-अपने आर्थिक-कूटनीतिक हित हैं। इन स्थितियों में सर्वोत्तम उपाय स्वदेशी को बल देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज की वैश्विक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो भागवत के विचार और भी प्रासंगिक हो उठते हैं। दुनिया हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से त्रस्त है। पर्यावरण संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। मानसिक तनाव और आत्मकेंद्रित जीवन-शैली ने मानव को भीतर से खोखला कर दिया है। इन परिस्थितियों में भारत ही वह देश है, जो एक वैकल्पिक जीवन-दर्शन दे सकता है। भारत के पास भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक समृद्धि की धरोहर है। यही धरोहर भारत को विश्वगुरु बनने की पात्रता प्रदान करती है। संघ की शताब्दी वर्ष की सम्पूर्णता का उद्घोष केवल संघ के स्वयंसेवकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए एक संदेश है। यह संदेश है- स्वावलम्बी एवं स्वदेशी भावना को बदल देना, नए मनुष्य का निर्माण करना, गरीब को उठाना, धर्मों को जोड़ना, समाज में समरसता स्थापित करना और हिंदुत्व की व्यापक जीवन दृष्टि के आधार पर विश्व को दिशा देना।

प्रेरणा

जिन्होंने अंधेरे में भी उजाला खोजा: अंतोन चेखव की संघर्ष से सृजन की कहानी

रूस की ठंडी हवाओं और संघर्षों से भरे उस दौर में, एक छोटा-सा परिवार जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। घर में न धन था, न संसाधन, न ही कोई ऐसी सुविधा जो एक सामान्य जीवन को भी सरल बना सके। लेकिन इसी अभाव के घर में जन्मा एक बालक, जिसे दुनिया बाद में महान कथाकार अंतोन पावलोविच चेखव के नाम से जानेगी, उसने ये साबित किया कि जब भीतर जिद, संवेदना और विश्वास हो—तो कोई भी हालात इंसान को थाम नहीं सकते।

यह घटना तब की है जब चेखव किशोर अवस्था में थे। एक रात उनकी मां को एक ग्राहक के लिए रूमाल तैयार करना था। घर में सिलाई मशीन नहीं थी। इस कारण उन्हें पूरी रात अपनी दुखती आंखों और थके हुए हाथों से हाथ से ही रूमाल की कढ़ाई करनी पड़ी। आंखें लाल हो चुकी थीं, दर्द से भारी थीं, फिर भी माँ ने कोई शिकायत नहीं की। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रही थीं—चुपचाप, बिना थमे। चेखव यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। यह दृश्य केवल एक पीड़ित मां का नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का वह मोड़ था जहाँ उन्होंने तय किया कि अब वह केवल तमाशबीन नहीं रहेंगे। उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी प्रतिभा और ज्ञान से परिवार की दशा बदलेंगे। अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने अपने एक जूनियर को मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवाना शुरू किया, जिससे उन्हें थोड़ी आमदनी होने लगी। इस कार्य ने न केवल आर्थिक सहारा दिया, बल्कि उनके भीतर एक डॉक्टर बनने की भावना को भी जीवंत कर दिया। उनका यह दोहरा संघर्ष—साहित्य में लेखनी चलाने का और चिकित्सा में सेवा भाव का—धीरे-धीरे उन्हें एक नई पहचान दिलाने लगा।

इक्कीस साल की आयु तक वह न केवल एक योग्य चिकित्सक बन चुके थे, बल्कि साहित्यिक दुनिया में भी उनकी लेखनी की गूंज सुनाई देने लगी थी। उनकी कहानियाँ सीधी-सादी भाषा में, परंतु जीवन के जटिल सत्य को उजागर करने वाली होती थीं। वे हर आम व्यक्ति की पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीद को अपनी कहानियों में जिंदा कर देते थे।

चेखव से मिलने आने वाले लोग उनसे अक्सर पूछते थे – इस कठिन जीवन से आपने इतना प्रकाश कैसे खींचा?

चेखव तब मुस्कुराते हुए एक ही उत्तर देते –

विश्वास ही वह शक्ति है जिससे हम उजड़ी हुई दुनिया में भी उजाला फैला सकते हैं।

फिर वे ठहर कर कहते –

हम समस्याओं से नहीं हारते, हम अपनी सोच की कमजोरी से हारते हैं। अगर हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचान लें, तो कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि हमें रोक सके। दरअसल, समस्याएं हमारी परीक्षा लेने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती हैं।

यह कथन किसी किताब से नहीं लिया गया था। यह उनकी जमी हुई बर्फ के बीच से फूटी हुई आत्मा की आवाज थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने मां को पीड़ित देखा, जिसने आर्थिक तंगी को नापा, जिसने न बीमारी से डरा न बेरोजगारी से—वह दुनिया को यह सिखा गया कि जीवन एक अवसर है, और हर कठिनाई उसमें नया अध्याय जोड़ने आती है।

आज जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो हमें अंतोन चेखव को याद करना चाहिए। वह हमें यह नहीं सिखाते कि दर्द से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सिखाते हैं कि दर्द को कैसे सार्थक बनाया जाए।

क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो—अगर भीतर विश्वास की लौ हो, तो उजाला वहीं से फूटता है।

कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें चिंताजनक, दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना सबसे बड़ी जरूरत

मध्य प्रदेश और राजस्थान से बच्चों की मौतों की जो खबरें आईं, उन्होंने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। महज़ खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारी के लिए दी जाने वाली खांसी की दवा, बच्चों के जीवन पर इतनी घातक साबित होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में 9 बच्चों की मौत और राजस्थान के विभिन्न जिलों में 3 बच्चों की मौत ने चिकित्सा व्यवस्था, दवा नियमन और प्रशासनिक सतर्कता, तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ़ किया है कि मध्य प्रदेश से लिए गए 19 सैंपल्स में से 9 की जांच रिपोर्ट में डायथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल जैसी जानलेवा रसायनों की मौजूदगी नहीं पाई गई है। हम आपको बता दें कि यह वही तत्व हैं जिन्होंने 2019 में जम्मू और 2022-23 में गाम्बिया व उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भारतीय दवाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर विवाद ख

हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के पारासिया और आसपास के गांवों में अगस्त के अंत से बच्चों में सर्दी-खांसी और हल्का बुखार देखा गया। डॉक्टरों ने उन्हें साधारण खांसी की सिरप और दवाएं दीं। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, पेशाब कम होना, शरीर में सूजन और किडनी से जुड़ी जटिलताएं बढ़ने लगीं। नतीजतन, नौ मासूमों की जान चली गई और पांच बच्चे नागपुर में विशेष इलाज के लिए भर्ती हैं।

राजस्थान में हालात और भी उलझे हुए हैं। सरकार द्वारा मुफ़्त दवा योजना में बांटी जा रही डेक्स्ट्रोमेथॉर्फ़न-आधारित सिरप लेने के बाद सीकर, भरतपुर और बांसवाड़ा के कई बच्चों में गंभीर लक्षण दिखे, जैसे- उल्टी, चक्कर, बेहोशी और घबराहट। इनमें तीन बच्चों की मौत भी हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भले ही इन मौतों को सीधे दवा से जोड़ने से इंकार किया हो, लेकिन तत्काल प्रभाव से संबंधित कंपनियों की दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है। जयपुर स्थित Kaysans Pharma की 19 दवाओं पर रोक इसीलिए लगाई गई क्योंकि कंपनी की दवा गुणवत्ता का रिकॉर्ड पहले से संदिग्ध रहा है। कंपनी के 10,119 सैंपल्स में से 42 घटिया पाए गए थे। देखा जाये तो भारत दुनिया का "फार्मेसी हब" कहलाता है, लेकिन समय-समय पर घटिया दवाओं के मामले हमारी छवि को धूमिल करते हैं। सवाल यह है कि जब दवा कंपनियों के खिलाफ पहले से संदिग्ध रिपोर्ट थीं, तो उन्हें सरकारी योजनाओं में शामिल क्यों किया गया? साथ ही विशेषज्ञ लगातार कहते आए हैं कि दो साल से छोटे बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में अक्सर बिना उचित परामर्श के इन्हें दिया जाता है। यही लापरवाही जानलेवा बनती है। केंद्र सरकार ने तो फिलहाल MP के सैंपल्स को सुरक्षित बताया है, लेकिन बाकी रिपोर्टें अभी आनी बाकी हैं। जब तक सभी जांच पूरी नहीं होतीं, तब तक कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी होगा। फिर भी राज्यों और केंद्र के बयानों में तालमेल की कमी आम जनता की चिंता बढ़ाती है।

अक्सर देखने में आता है कि ग्रामीण परिवार खांसी-जुकाम को हल्का समझकर बच्चों को अपने आप ही दवाएं दे देते हैं। यहां यह समझना ज़रूरी है कि बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है और कई दवाओं के दुष्प्रभाव घातक हो सकते हैं।

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ़ हिदायत दी है कि दो साल से छोटे बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं न दी जाएं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। आगे की राह क्या हो यदि इस पर गौर करें तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जिन कंपनियों का रिकॉर्ड खराब है, उनकी दवाओं को सरकारी आपूर्ति श्रृंखला से तत्काल हटाया जाना चाहिए। साथ ही, फार्मा कंपनियों के लिए कठोर ऑडिट और बार-बार टेस्टिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके अलावा, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका अहम है, वहां दवाओं के सही उपयोग और खुराक के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन दी जानी चाहिए। साथ ही परिवारों को बताना चाहिए कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी-जुकाम की सिरप न दें। साधारण घरेलू देखभाल जैसे भाप, गर्म पानी और साफ-सफाई कई बार ज्यादा प्रभावी होती है। इसके अलावा, मौत के मामलों पर स्पष्ट रिपोर्ट जनता के सामने समय पर लाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, ताकि अफवाहें और डर न फैलें। देखा जाये तो यह केवल छिंदवाड़ा या राजस्थान का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा यह संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दवा निगरानी प्रणाली उतनी सख़्त है, जितनी होनी चाहिए? क्या हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सतर्कता और ज़िम्मेदारी को पर्याप्त महत्व दिया है? बहरहाल, इन सवालों के जवाब केवल जांच रिपोर्टों से नहीं, बल्कि प्रणालीगत सुधारों से आएंगे। आज ज़रूरी है कि हर मौत को गम्भीरता से लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई मासूम अपनी जान न गंवाए। यह हादसा केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की अनिवार्य पुकार है।

अभियान

मानसून में तुलसी को मत छूना — जानिए दादी-नानी की इस परंपरा के पीछे का गहरा कारण

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा केवल एक औषधीय जड़ी नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा "वृंदा देवी" माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का वास होता है। तुलसी की उपस्थिति ही घर में पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आपने भी अक्सर दादी-नानी को यह कहते सुना होगा कि "बरसात के मौसम में तुलसी को मत छूओ, यह अशुभ होता है।" तो आखिर मानसून में तुलसी को छूने की मनाही क्यों है — इसका रहस्य धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से अत्यंत रोचक है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रावण मास में तुलसी माता विश्राम करती हैं। यह समय तुलसी की 'निद्रा अवधि' या 'व्रज यात्रा' कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान तुलसी माता भगवान विष्णु के साथ ब्रजभूमि की यात्रा पर जाती हैं और अपने भक्तों से कुछ समय के लिए दूर रहती हैं। इसलिए बरसात के महीनों में तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना माता के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। यही कारण है कि इस काल में तुलसी को जल चढ़ाने या उसके पत्तों को पूजा में अर्पित करने से परहेज़ किया जाता है।

शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भागवत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि "जो व्यक्ति तुलसी के विश्राम काल में उसे स्पर्श करता है, वह पुण्य के बजाय अनजाने में अपमान का भागी बनता है।" तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा और मर्यादा बनाए रखना भक्त का धर्म है।

दूसरी ओर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस परंपरा का समर्थन करता है। मानसून में वातावरण अत्यधिक नम और आर्द्र हो जाता है। इस समय तुलसी के पत्तों पर जल, मिट्टी, फफूंदी और सूक्ष्म कीटाणु पनपने लगते हैं। जब हम गीली तुलसी को छूते हैं या उसके पत्ते तोड़ते हैं, तो पौधा संक्रमण की चपेट में आ सकता है, जिससे उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। यही कारण है कि बरसात के मौसम में तुलसी को अधिक छूना या पानी डालना पौधे के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है।

इस प्रकार, दादी-नानी की यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे अनुभव और वैज्ञानिक समझ का मिश्रण है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के हर नियम का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। तुलसी माता की पूजा करने का सर्वोत्तम समय कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, जब 'तुलसी विवाह' के बाद तुलसी का पुनः पूजन किया जाता है। तब तक तुलसी माता विश्राम करती हैं — और इस अवधि में उन्हें छूने से विराम ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

इसलिए, जब अगली बार दादी कहें "बरसात में तुलसी को मत छूना", तो समझ लीजिए — यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि धर्म, विज्ञान और संवेदनशीलता का सुंदर संगम है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

भारत बनेगा एआई महाशक्ति — ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मोदी के विजन से दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा भारत

(जीएनएस)। नई दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भारत की डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदला है, बल्कि अब वह एआई और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 महामारी के कठिन दौर ने दुनिया को यह सिखाया कि उद्योग, शिक्षा और संचार — सब कुछ एक छोटी सी माइक्रोचिप पर निर्भर हो गया है। भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदला और 76,000 करोड़ के "भारत सेमीकंडक्टर मिशन" की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, और अब तक इस क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। 85,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे भारत आत्मनिर्भर और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बन रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज विश्व आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संकट और मुद्रास्फीति जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन भारत ने इन परिस्थितियों में भी 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया को चकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है और "न्याय, समानता और साझा विकास" का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

सिंधिया ने बताया कि भारत में आज 1.22 अरब टेलीफोन ग्राहक और 94.4 करोड़ ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं। यह पिछले दस वर्षों में पंद्रह गुना वृद्धि है। भारत ने केवल 22 महीनों में 99.8% जिलों में 5G नेटवर्क पहुँचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर — जैसे कि UPI — अब सालाना 260 अरब से अधिक लेनदेन कर रहे हैं, जो दुनिया के कुल डिजिटल लेनदेन का लगभग 46% हिस्सा है।

प्रधानमंत्री मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" मिशन की चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक युगांतरकारी परिवर्तन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक लॉन्च किया, जिसे सी-डॉट, टेजस नेटवर्क्स और टीसीएस के सहयोग से विकसित किया गया है। आज देश के कोने-कोने में 92,564 नए टावर स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे भारत उन पाँच देशों में शामिल हो गया है जो पूरी तरह स्वदेशी टेलीकॉम इकोसिस्टम तैयार करने में सक्षम हैं।

उन्होंने बताया कि बीएसएनएल 17 साल बाद फिर से लाभ में आया है और उसका ग्राहक आधार 78 लाख से बढ़कर 2.2 करोड़ तक पहुँच गया है। अब सभी टावर 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं, जिससे भारत की डिजिटल शक्ति नए स्तर पर पहुँचेगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि यह भविष्य की संचार क्रांति का केंद्र है। "इंडिया एआई मिशन" के तहत भारत घरेलू एआई मॉडल, कम्प्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को सशक्त बना रहा है। निजी क्षेत्र द्वारा अब तक 20,000 करोड़ मूल्य के 38,000 GPUs स्थापित किए जा चुके हैं और कुल निवेश $10 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य ऐसा एआई विकसित करना है जो भारतीय भाषाओं और भारतीय जरूरतों के अनुरूप हो, ताकि तकनीक का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे।

अपने वक्तव्य के अंत में सिंधिया ने कहा कि भारत की प्रगति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक भी है। भारत आज फिनटेक, दूरसंचार, अक्षय ऊर्जा, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी है। मोबाइल डेटा उपयोग में विश्व में प्रथम, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और मोबाइल निर्माण में द्वितीय, स्टार्टअप्स में तृतीय और अक्षय ऊर्जा क्षमता में चतुर्थ स्थान भारत की इस अद्भुत यात्रा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत 2027 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, और यह उपलब्धि केवल तकनीक से नहीं, बल्कि "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना और स्वदेशी नवाचार की शक्ति से संभव हो रही है। सिंधिया ने अपने भाषण का समापन इन शब्दों में किया — "भारत अब केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है — जो विश्व को समृद्धि, स्थिरता और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखा रहा है।"

सूरत से अगवा बच्चा 72 घंटे बाद मिला — 1000 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल से पुलिस ने वलसाड में खोज निकाला मासूम

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस ने तीन दिन की अथक मेहनत से एक मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। यह मामला उस समय सामने आया जब एक महिला ने फुटपाथ से खेलते हुए दो साल के बच्चे को अगवा कर लिया था। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो लगातार तीन दिन तक चला। पुलिस के अनुसार, यह घटना सूरत के उधना इलाके की है, जहां शुक्रवार की रात एक मजदूर परिवार का बच्चा फुटपाथ पर खेलते हुए अचानक लापता हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताते हुए जांच शुरू की और

शहर के प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और बाजार क्षेत्रों के करीब 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन वीडियो में पुलिस को एक संदिग्ध महिला दिखाई दी जो बच्चे को गोद में लेकर बस स्टैंड की ओर जाती नजर आई। जांच टीम ने फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की और यह पता लगाया कि वह बस से वलसाड की दिशा में गई थी। इसके बाद सूरत पुलिस की एक विशेष टीम वलसाड रवाना हुई और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। लगातार 72 घंटे के अथक प्रयास के बाद सोमवार देर रात पुलिस ने वलसाड के परेरा इलाके में एक झोपड़ी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। महिला को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके कोई संतान नहीं थी और उसने बच्चे को अपने पास रखने की नीयत से उठाया था।

सूरत पुलिस आयुक्त ने इस मामले में शामिल अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह "एक उत्कृष्ट टीमवर्क और तकनीक के संयोजन से हासिल की गई सफलता" है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बच्चे की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और हर संभव संसाधन जुटाकर तीन दिन के भीतर उसे वापस लाने में सफलता पाई। बच्चे को मेडिकल जांच के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। जब पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार के हवाले किया, तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में खुशी के आँसू थे। बच्चे की माँ ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि "भगवान के बाद पुलिस ने मेरा बेटा लौटाया है।"

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि आधुनिक तकनीक, जैसे कि सीसीटीवी नेटवर्क और डाटा एनालिसिस, अब अपराधों की जाँच में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूरत पुलिस के इस त्वरित और मानवीय प्रयास ने न केवल एक मासूम की जान बचाई बल्कि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है।

राधनपुर में भीषण सड़क हादसा — रॉन्ग साइड से आए ट्रेलर ने मचाई तबाही, चार लोगों की मौके पर मौत

(जीएनएस)। राधनपुर (गुजरात)। पाटण जिले के राधनपुर हाईवे पर सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब रॉन्ग साइड से आ रहा एक ट्रेलर सामने से आ रही पिकअप वैन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे से आ रही तीन अन्य गाड़ियां भी उसमें जा भिड़ीं। इस भीषण टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राधनपुर-मोरबी हाईवे घंटों तक जाम रहा और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ, जब भुज की ओर जा रहा एक भारी ट्रेलर सड़क के एक हिस्से पर मरम्मत कार्य के कारण बंद मार्ग को पार करने के लिए रॉन्ग साइड से चला गया। उसी समय सामने से आ रही पिकअप वैन ट्रेलर से आमने-सामने भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके पीछे चल रही कार और दो अन्य गाड़ियां भी अनियंत्रित होकर उसमें जा घुसीं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद आसपास धूल और धुएं का गुबार छा गया, कई लोग गाड़ियों में फंस गए थे और चीख-पुकार मच गई थी। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और घायलों को गाड़ियों से निकालने का प्रयास किया। इसके बाद राधनपुर पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।

चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सात घायलों को तत्काल राधनपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित किया जा रहा है।

करसनभाई के एक विचार ने रची भारतीय उद्योग में एक महान विरासत, उनकी यात्रा VGRC में देगी उद्यमियों को प्रेरणा

- कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करसनभाई पटेल
- बेहतरीन गुणवत्ता और किफ़ायती मूल्य का संगम बनाने वाली 'निरमा' ने बनाई भारतीय उपभोक्ताओं के बीच नई पहचान
- उद्योग के साथ-साथ दूरदर्शी शिक्षाविद् और निष्ठावान समाजसेवी भी थे करसनभाई पटेल
- मंडाली और छत्राल में स्थापित विशाल औद्योगिक केंद्रों से स्थानीय विकास और रोजगार में दिया उत्कृष्ट योगदान

(जीएनएस)। गांधीनगर, : उत्तर गुजरात के एक साधारण किसान परिवार से निकले एक युवक ने वह कर दिखाया, जिसे आज दुनिया "भारतीय उद्यमशीलता की मिसाल" के रूप में पहचानती है। श्री करसनभाई पटेल एक ऐसे विज्ञान स्नातक जिन्होंने अपने घर से शुरू किया वह सफर, जो आज अरबों डॉलर के औद्योगिक साम्राज्य तक पहुँचा।

रूपपुर से अहमदाबाद तक: एक तकनीशियन से उद्यमी तक का सफर

1945 में उत्तर गुजरात के रूपपुर गाँव में जन्मे करसनभाई पटेल ने रसायन विज्ञान में बी.एससी. की डिग्री हासिल की। अहमदाबाद के न्यू कॉटन मिल्स में लैब तकनीशियन के रूप में नौकरी करते हुए उन्होंने 1969 में अपने घर से ही डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। सुबह दफ़्तर जाने से पहले वे अपनी साइकिल पर शहर में घूमते और अपने हाथों से बनाए डिटर्जेंट के पैकेट घर-घर बेचते। उन्होंने इस उत्पाद का नाम अपनी स्वर्गीय पुत्री के नाम "निरमा", पर रखा जो आगे चलकर भारत की सबसे लोकप्रिय FMCG ब्रांडों में से एक बनी।

उत्तर गुजरात में औद्योगिक परिवर्तन का सूत्रपात

श्री करसनभाई पटेल ने अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बनाया, बल्कि इसे सामाजिक विकास का माध्यम बनाया। उन्होंने मंडाली और छत्राल जैसे उत्तर गुजरात के इलाकों में विशाल औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। इन इकाइयों ने हज़ारों स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फलने-फूलने का अवसर दिया।

'निरमा' ने उस दौर में भारतीय

उपभोक्ताओं को एक ऐसा विकल्प दिया, जो गुणवत्ता और किफ़ायत का अद्भुत संगम था। जहाँ विदेशी ब्रांड महंगे थे, वहीं 'निरमा' ने साधारण परिवारों को सुलभ मूल्य पर बेहतरीन गुणवत्ता उपलब्ध कराई। यही सादगी और भरोसा उसका सबसे बड़ा विज्ञापन बन गया। लोगों की जुबान से निकली सिफ़ारिशें ही उसके प्रचार का माध्यम बनीं। देखते ही देखते 'निरमा' हर घर की जरूरत, हर मां की पसंद और हर भारतीय की पहचान बन गया। इस अपार सफलता के बाद करसनभाई पटेल ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरे समर्पण के साथ अपने सपने ''निरमा'' को राष्ट्रव्यापी उद्योग का स्वरूप देने के लिए जुट गए।

शिक्षा के माध्यम से समाज निर्माण का दूरदर्शी संकल्प

करसनभाई पटेल का मानना था कि किसी भी समाज की सच्ची समृद्धि उसकी शिक्षा से ही संभव है। इसी भावना के साथ उन्होंने निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की ताकि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सके। इस पहल के अंतर्गत निरमा यूनिवर्सिटी और निरमा विद्याविहार जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हुए, जो आज इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, डिज़ाइन, फार्मेसी और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। कर्सनभाई पटेल ने यह सिद्ध कर दिखाया कि बिना घर छोड़े और बिना सपनों को छोड़े भी विश्वस्तरीय शिक्षा अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा सकती है।

करसनभाई पटेल: एक प्रेरक

उद्यमी, एक दूरदर्शी शिक्षाविद्, एक निष्ठावान समाजसेवी

करसनभाई पटेल ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब समर्पण, दृष्टि और कर्म एक साथ चलते हैं, तो सफलता केवल व्यक्ति की नहीं, समाज की भी होती है। उद्योग, शिक्षा और समाज तीनों क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। 1990 में उन्हें उद्योग रत्न पुरस्कार, 1998 में गुजरात बिज़नेसमैन अवॉर्ड, 2006 में अर्न्स्ट एंड यंग लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, 2009 में सरदार वल्लभभाई पटेल विश्व प्रतिभा अवॉर्ड और 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी (यूएसए) और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इंदौर) ने भी उन्हें मानद उपाधियाँ प्रदान कर उनके बहुआयामी योगदान को सम्मानित किया है।

आगमी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनेगी प्रेरणा और नवाचार की नई दिशा

आगामी 9-10 अक्टूबर को उत्तर गुजरात के मेहसाणा में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) उत्तर गुजरात के ऐसे ही दूरदर्शी उद्यमियों की प्रेरक यात्राओं को नमन करने का अवसर है जिन्होंने स्थानीय संसाधनों, नवाचार और अटूट संकल्प के बल पर वैश्विक पहचान बनाई। साथ ही, यह आयोजन न केवल उत्तर गुजरात की उद्यमशीलता भावना का उत्सव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरक संदेश भी देता है कि जब एक विचार कर्म और निष्ठा से जुड़ता है, तो वह सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि परिवर्तन की कहानी बन जाता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में घुमंतू और विमुक्त जातियों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन

ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया आदि की उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अहमदाबाद में आयोजित घुमंतू और विमुक्त जातियों के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में साफ तौर पर कहा कि जिनको कोई पूछता भी नहीं था, ऐसे अंत्योदय, गरीब और वंचितों को मोदी साहब ने पूजा है।

डीएनटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस महासम्मेलन राज्य भर से घुमंतू और विमुक्त जातियों के लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में यह सवाल था कि घुमंतू और विमुक्त जाति का समाज आगे बढ़ेगा तो आखिर कब बढ़ेगा, लेकिन हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व मिला और प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज को साथ रखकर चलने से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का ध्येय साकार हुआ है।

उन्होंने कहा कि छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में विचार कर सरकारी योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए हाशिये पर खड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को केंद्र में रखकर उन्हें विकास के साथ जोड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने घुमंतू और विमुक्त जातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने आपके बेटे-बेटियां पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। पिछले तीन वर्षों में घुमंतू और विमुक्त जाति के 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 297 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता और 8448 लाभार्थियों को 105 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और दुनिया के साथ-साथ समय की जो मांग है, उसके मुताबिक बच्चे कदम से कदम मिलाकर पढ़-लिखकर कर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जहां भी आवश्यकता होगी, वहां सरकार आपके साथ खड़े रहने को तैयार है।

उन्होंने इस समाज की बहनों और माताओं को भी स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सभी समाजों को भी इसमें जुड़ना होगा।

विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने हेतु सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं में संतृप्तिकरण यानी सैचुरेशन के दृष्टिकोण से साथ खड़ी है ताकि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी मुख्यधारा में शामिल हो सके।

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण जनजीवन को बहुत लाभ हो रहा है।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहारी सीजन में स्वदेशी वस्तुओं की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को गति देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घुमंतू और विमुक्त जाति के लोगों को स्थायी ठिकाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें 'खुद का घर' देने की शुरुआत की थी। उन्होंने आगे कहा कि 28 घुमंतू और 12 विमुक्त जातियों सहित कुल 40 जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत अधिक पिछड़ी हैं, तब राज्य सरकार ने 2015 में ऐसे लोगों के लिए निगम का गठन किया था।

श्रीमती बाबरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने घुमंतू और विमुक्त जाति के बच्चों की शिक्षा की चिंता कर उन्हें स्कॉलरशिप और अन्य शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अंतिम छोर के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

> प्रधानमंत्री ने घुमंतू और विमुक्त जातियों के लिए अनेक कल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से इस बात को साकार किया है कि 'जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है'
>
> -मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेता को अपने व्यवसाय के लिए बैंक से आसान तरीके से ऋण मिल सके।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों द्वारा पद्मश्री भानुभाई चितारा का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण, राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्री मयंक नायक, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री पेरकभाई शाह, श्री भरतभाई पटणी, श्री प्रवीणभाई धुगे, श्री सागरभाई रायका और घुमंतू एवं विमुक्त जातियों के राज्य भर से आए अग्रणियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन ने पेश की सेवा की मिसाल, नन्द गोपाल नन्दी बोले – कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है समाज

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने कहा कि वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन आज समाज के कमजोर और निर्बल वर्ग के उत्थान में आदर्श भूमिका निभा रहा है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित नेशनल कॉनक्लेव में उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल दान या सहायता नहीं, बल्कि स्थायी आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करना है। इस सम्मेलन में प्रयागराज के 60 प्रतिनिधि और देशभर के नामी व्यापारिक एवं सामाजिक घराने शामिल हुए।

नन्दी ने कहा कि वैश्य समाज की ताकत सदियों से व्यापार, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व में रही है। यही भावना आज भी नयी पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के 11 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नन्दी सेवा संस्थान और वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन की ओर से आधुनिक ठेले प्रदान किए गए, ताकि ये परिवार गरिमा के साथ अपनी आजीविका चला सकें।

इसके अलावा कई परिवारों को व्यापारिक सहायता दी गई — एक परिवार को पाँच लाख रुपये, दो परिवारों को दो-दो लाख रुपये और एक व्यापारी को सात लाख रुपये की सहायता दी गई। इससे उन्हें अपने छोटे व्यवसाय को विस्तार देने का अवसर मिलेगा। नन्दी ने कहा, "यह मदद केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।"

नैनी क्षेत्र के मूक-बधिर दंपति संजय अग्रवाल और उनकी पत्नी को अपनी कोल्डड्रिंक और नमकीन की दुकान को बढ़ाने के लिए दो लाख रुपये की विशेष सहायता दी गई। इसी प्रकार आग से क्षतिग्रस्त दुकान को पुनः स्थापित करने के लिए रामलाल को पाँच लाख रुपये तथा अनुज अग्रहरी को व्यापार बढ़ाने के लिए सात लाख रुपये प्रदान किए गए। शहडोल की रूमा गुप्ता को भी दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई।

सम्मेलन में प्रयागराज के 11 श्रमजीवियों — शुभम साहू, राकेश कुमार केसरवानी, सीताराम चौरसिया, बुद्ध मती जायसवाल, कोमल केसरवानी, गेंदा लाल गुप्ता, अजय कुमार साहू, धनुषधारी, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, रिकी केसरवानी और आदित्य — को आधुनिक कार्ट-ठेले दिए गए। इन ठेलों में सौर ऊर्जा पैनल, स्टोरेज कैबिनेट और आधुनिक डिज़ाइन जैसी सुविधाएँ हैं, जिससे वे अधिक ग्राहकों तक पहुँच सकेंगे और अपने परिवारों को आर्थिक स्थिरता दे पाएंगे। नन्दी ने कहा, "हम केवल मदद नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें व्यापार से जोड़ रहे हैं ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मनिर्भर बना सकें। वैश्य समाज की यही पहचान है — उद्योग, सेवा और समर्पण।"

कॉनक्लेव में देश के कई उद्योगपतियों और समाजसेवियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को भव्यता दी। इसमें केंट आरओ सिस्टम के चेयरमैन महेश गुप्ता, हल्दीराम ग्रुप के मनोहर लाल अग्रवाल, क्रिस्टल ग्रुप के नन्द किशोर अग्रवाल, मल्टीकलर स्टील्स ग्रुप के राजेश गुप्ता, निराला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सुरेश गर्ग, लोहिया ग्रुप के विनीत गुप्ता, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नन्दी सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियाँ उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के अंत में नन्दी ने कहा, "वैश्य समाज केवल उद्योग जगत की रीढ़ नहीं, बल्कि समाज के कमजोर तबके का सहारा भी है। जब हम किसी एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम एक संपूर्ण समाज को सशक्त करते हैं।"

डासना जेल से बंदी को भगाने की साजिश नाकाम, दो सिपाही गिरफ्तार — निजी कार से पेशी पर ले जाने का था प्लान

(जीएनएस)। नोएडा। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर एक बार फिर दाग लगाने वाला मामला गाजियाबाद में सामने आया है। डासना जेल से एक बंदी को फरार कराने की साजिश को जेल प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस मामले में यूपी पुलिस के दो सिपाहियों — राहुल कुमार और सचिन — को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर आरोप है कि वे सरकारी गाड़ी के बजाय अपनी निजी कार से बंदी को जेल से बाहर ले जाने पहुंचे थे।

अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि दोनों आरोपी सिपाही पुलिस लाइन गाजियाबाद में तैनात हैं और इनकी ड्यूटी जेल से बंदियों को अदालत में पेशी के लिए ले जाने की थी। 4 अक्टूबर 2025 को डासना जेल से छह बंदियों की पेशी निर्धारित थी, लेकिन ये दोनों केवल एक बंदी बिजेंद्र को नोएडा अदालत ले जाने पर अड़े हुए थे। जेल अधिकारियों को जब यह बात संदिग्ध लगी तो उन्होंने रवानगी रजिस्टर की जांच कराई। जांच में पता चला कि उस दिन गौतमबुद्धनगर न्यायालय के लिए कोई पेशी निर्धारित ही नहीं थी। संदेह गहराने पर जेल अधीक्षक ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों सिपाही अपनी निजी कार से बंदी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार यह कार्य केवल सरकारी वाहन और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर की तहरीर पर थाना कविनगर में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद कविनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि "वर्दी का दुरुपयोग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।"

जेल प्रशासन की सतर्कता से यह गंभीर साजिश समय रहते उजागर हो गई, जिससे एक बंदी के फरार होने की बड़ी घटना टल गई। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता थी या नहीं।

सांसद रवि किशन ने गोरखपुर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की, बोले – "स्वस्थ व्यवहार अपनाएं, रोग को हराएं"

(जीएनएस)। गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में रविवार को सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने 'विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान' की शुरुआत की। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पर्यटन भवन से हरी झंडी दिखाकर इस जनजागरूकता रथ को रवाना किया, जो 5 से 31 अक्टूबर तक गांव-गांव और शहर के वार्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का संदेश फैलाएगा।

इस अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सांसद रवि किशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नगर निगम कर्मचारियों, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीमों को शपथ दिलाई कि वे लोगों को "घर-घर दस्तक अभियान—स्वस्थ व्यवहार अपनाना है, संचारी रोग को हराना है" का संदेश देंगी। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से बचाव केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने घर और आसपास सफाई रखे और बीमारियों को फैलने से रोके।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' ने देश में एक जनआंदोलन खड़ा किया है और गोरखपुर इस दिशा में मिसाल बन सकता है, यदि हर परिवार स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना ले। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जलभराव, गंदगी और खुले में कचरा फेंकने जैसी आदतों को त्यागें, ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफलाइटिस जैसे रोगों से शहर को मुक्त किया जा सके।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि इस वर्ष 2025 में अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल 21 इंसेफलाइटिस के मरीज भर्ती हुए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि यह परिणाम प्रशासनिक प्रयासों, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी और आम जनता के सहयोग से संभव हुआ है।

उन्होंने बताया कि अभियान की दूसरी चरण 'दस्तक अभियान' 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को बुखार, डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफलाइटिस, चिकनगुनिया और अन्य संचारी रोगों के लक्षणों और बचाव के उपायों की जानकारी देंगी। किसी भी रोगी की पहचान होने पर तत्काल उसे सरकारी अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसीएमओ डॉ. राजेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र पांडेय, बीएसए रामेंद्र सिंह, डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह, पार्षद अजय राय और रढनजन्य जुगनू समेत अनेक अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर सांसद रवि किशन ने कहा, "यह केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य का संकल्प है। यदि जनता और प्रशासन एकजुट होकर काम करें, तो गोरखपुर को पूर्ण रूप से रोगमुक्त बनाना कोई सपना नहीं, बल्कि साकार लक्ष्य होगा।"

उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरी की अफवाहों से फैली दहशत, पुलिस-प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से शुरू हुई ड्रोन चोरी की अफवाहें अब पूर्वी जिलों तक फैल गई हैं। रायबरेली, कानपुर, इटावा और बलिया समेत कई जिलों में 'ड्रोन चोर' की कहानियों ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में भय और संदेह का माहौल बना दिया है। रायबरेली में शनिवार को फतेहपुर के 38 वर्षीय हरिओम की कथित रूप से पिटाई कर हत्या करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, हरिओम मानसिक रूप से विक्षिप्त था और ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे ड्रोन चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य समझकर हमला कर दिया। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि इलाके में अफवाहें फैल रही थीं, इसलिए ऊंचाहार थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में तबादला कर दिया गया।

कानपुर के बिधनू इलाके में भीड़ ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति को पिटाई की, क्योंकि उसे ड्रोन ऑपरेटर समझ लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि कानपुर में ड्रोन से चोरी की कोई सत्यापित घटना नहीं हुई है और नागरिकों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। अफवाहें अब हमीरपुर, प्रतापगढ़, इटावा, देवरिया और बलिया तक फैल गई हैं। ग्रामीण रात में चौकसी बरत रहे हैं। हमीरपुर की पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने कहा कि किसी भी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांवों में भय का माहौल है। लखनऊ के अधिकारी इसे 'सामूहिक भय सिंड्रोम' बता रहे हैं। राज्य की 'यूपी-112' आपातकालीन लाइन पर ड्रोन चोरी की सूचनाओं के कॉल में भारी वृद्धि हुई है, जबकि वास्तविक अपराध की कोई पुष्टि नहीं हुई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में सभी जिलों को ड्रोन रजिस्टर बनाए रखने, रात में ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने 1 अक्टूबर को बलरामपुर में कहा, "ड्रोन नाम पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और चोरी के नाम पर आतंक फैलाने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी।"

इटावा में परिवार रात में बारी-बारी से जाग रहे हैं। देवरिया में बच्चों को सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। बलिया में किसान आसमान में मशालें जलाकर सतर्कता बरत रहे हैं। गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं।

इस स्थिति से स्पष्ट है कि अफवाहों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनमानस में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, जबकि प्रशासन ने इस खतरे से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाया है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रखी है।

करूर भगदड़ की सच्चाई उजागर करेगी एसआईटी जांच: मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा है कि करूर में हुई भयावह भगदड़ की सच्चाई अब विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से सामने आएगी। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित यह जांच दल पूरी घटना की तह तक जाकर हर स्तर पर जवाबदेही तय करेगा। मुख्यमंत्री ने इस त्रासदी को लेकर चल रहे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर गहरा दुःख जताते हुए सभी से संयम और सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा, "करूर में हुई त्रासदी से हम सभी गहराई से व्यथित हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके आंसू देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से इस घटना की जांच कर रही है और उच्च न्यायालय के हर दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तमिलनाडु के नागरिकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस जांच से न केवल पूरी सच्चाई सामने आएगी बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु ने हमेशा देश के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। अब हम भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ऐसा ही मॉडल तैयार करेंगे, जिसे पूरा देश अपनाएगा।"

उन्होंने बताया कि नई एसओपी (Standard Operating Procedure) हितधारकों, विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी, ताकि किसी भी बड़े जनसमूह में सुरक्षा की चूक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उदाहरण बनेगा।"

राजनीतिक मतभेदों पर रोक लगाने की अपील करते हुए स्टालिन ने कहा कि इस समय एक-दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का समय है। उन्होंने कहा, "हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी न केवल तमिलनाडु में, बल्कि पूरे देश में दोबारा न हो।"

उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था। यह जांच दल 27 सितंबर को अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की गहन जांच करेगा। इस दुर्घटना में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस घटना से मिली सीख के आधार पर तमिलनाडु को भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा का नया मानक स्थापित करना होगा।

अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद जमींदोज, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

(जीएनएस)। अहमदाबाद। शहर के सरसपुर क्षेत्र में स्थित 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को अहमदाबाद महानगरपालिका द्वारा ढहाने का निर्णय लिया गया है। मस्जिद ट्रस्ट को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। मस्जिद को ढहाने का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बुलेट ट्रेन के टर्मिनल के लिए सड़क चौड़ी करना बताया गया है।

हाई कोर्ट ने महानगरपालिका के नोटिस को कानून सम्मत बताते हुए मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए महानगरपालिका को 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को ढहाकर सड़क चौड़ी करने की अनुमति दी।

मस्जिद ट्रस्ट ने दावा किया था कि वक्फ कानून के तहत इस मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि मस्जिद का अस्तित्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और 400 वर्ष पुरानी किसी इमारत को ढहाना अवैधानिक होगा। बावजूद इसके, हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के तर्कों को खारिज करते हुए महानगरपालिका के पक्ष में फैसला सुनाया।

इस निर्णय के बाद शहर में मस्जिद के ढहने और सड़क चौड़ीकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महानगरपालिका ने मस्जिद स्थल पर काम शुरू करने से पहले सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।

AI से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा निजी निवेश और सेवा निर्यात में तेज़ी की उम्मीद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया की मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांजिस्का ओहन्सॉर्गे ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति से सबसे बड़ा आर्थिक लाभ उठाने वाले देशों में से एक बन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि AI अपनाने से न केवल उत्पादकता और सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, बल्कि निजी निवेश (Private Investment) में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

4 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत में ओहन्सॉर्गे ने कहा कि भारत का AI रेडीनेस इंडेक्स अब विकसित देशों के स्तर के करीब पहुंच चुका है, जो इस क्षेत्र में देश की तैयारी और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका सेवा क्षेत्र है, विशेषकर BPO और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जहाँ AI का प्रभाव सबसे पहले और सबसे गहराई से दिख रहा है।

उन्होंने बताया कि ChatGPT जैसे जेनरेटिव AI टूल्स के लॉन्च के बाद भारत में AI-स्किल से जुड़ी नौकरियों की मांग लगभग दोगुनी हो चुकी है और अब यह कुल नई नौकरी पोस्टिंग्स का करीब 12% हिस्सा बन गई हैं। यह अनुपात अन्य विकासशील देशों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

ओहन्सॉर्गे ने कहा कि AI के उपयोग ने भारत के सेवा निर्यात को भी अप्रत्याशित बढ़त दी है। ChatGPT के आने के बाद से कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुल सेवा निर्यात स्थिर रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपनी डिजिटल दक्षता और अंग्रेज़ी-भाषी कार्यबल के कारण वैश्विक स्तर पर नई मांगों को पूरा करने में सक्षम हो रहा है।

हालांकि उन्होंने यह भी माना कि महामारी के बाद भारत में निजी निवेश की गति कुछ धीमी रही है। सरकारी पूंजी निवेश ने विकास को सहारा दिया है, लेकिन अब AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर इस निवेश को गति देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि "धीमी वृद्धि के बावजूद भारत में निजी निवेश, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अब भी कहीं अधिक मज़बूत है।"

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संदर्भ में ओहन्सॉर्गे ने कहा कि यह वैश्विक मानकों की तुलना में फिलहाल कुछ कमजोर है, लेकिन भारत द्वारा किए जा रहे नए व्यापार समझौते और टैरिफ सुधार इसे गति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह अपने सेवा क्षेत्र और तकनीकी विशेषज्ञता के बल पर विकसित देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करे।

उनके अनुसार, मैक्सिको और वियतनाम जैसे देशों के व्यापारिक साझेदार उनकी GDP का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा अभी 12% GDP तक ही सीमित है। अगर भारत UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक व्यापार समझौते करता है, तो यह हिस्सेदारी कई गुना बढ़ सकती है।

ओहन्सॉर्गे ने विशेष रूप से भारत-UK ट्रेड एग्रीमेंट को "पिछले दशक का सबसे महत्वाकांक्षी" करार दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ टैरिफ कम करने की बात नहीं, बल्कि सेवाओं और श्रमिक गतिशीलता (Labour Mobility) को भी शामिल किया गया है — जो भारत जैसे देश के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। विश्व बैंक 7 अक्टूबर को दक्षिण एशिया पर अपनी नई रिपोर्ट जारी करने जा रहा है। जून में जारी पिछली रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि दर FY26 के लिए 6.5% और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% अनुमानित की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि AI का प्रसार इसी गति से होता रहा, तो यह अनुमान और भी ऊँचा जा सकता है — क्योंकि अब भारत सिर्फ एक "सेवा प्रदाता देश" नहीं, बल्कि "AI संचालित वैश्विक नवाचार केंद्र" के रूप में उभर रहा है।

दिवाली पर यात्रा का उत्सव बना नया ट्रेंड आस्था के साथ सैर-सपाटे की भी धूम

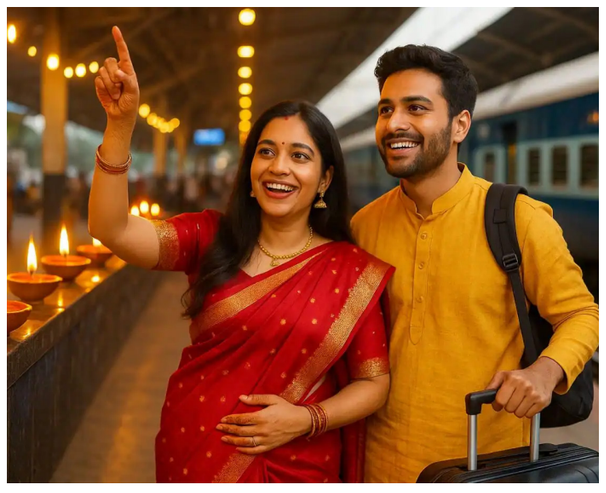

(जीएनएस)। मुंबई। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर देशभर में यात्रा का नया रुझान देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय अब त्योहार को न केवल पारिवारिक मिलन बल्कि सैर-सपाटे, लक्जरी छुट्टियों और आध्यात्मिक अनुभवों से भी जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 की दिवाली यात्रा के आंकड़े पिछले वर्षों के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक और CEO राजेश मागो के अनुसार, "दोस्तों और परिजनों से मिलने की परंपरा अब भी यात्रा का प्रमुख कारण बनी हुई है, लेकिन अब लोग उस अनुभव को और विशेष बनाने के लिए आध्यात्मिक या आरामदायक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि इस बार सबसे अधिक बुकिंग वाले घरेलू स्थलों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं। त्योहार सप्ताह के शुरुआत में पड़ने के कारण, बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार से ही छुट्टियां जोड़कर लंबी यात्राएं प्लान कर रहे हैं। राजेश मागो ने बताया कि तीर्थ यात्रा का चलन भी तेजी से बढ़ा है। "अब लोग केवल मिलन ही नहीं, बल्कि आस्था से भी अपने त्योहार को जोड़ रहे हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर यात्रियों की भीड़ पिछले साल की तुलना में 35% बढ़ गई है," उन्होंने कहा।

थॉमस कुक (इंडिया) के अध्यक्ष राजीव काले ने बताया कि इस बार दीपावली पर यात्राओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा परिवार — यानी तीन पीढ़ियाँ तक — एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोग अब तीन दिन की पारंपरिक छुट्टियों के बजाय 6 से 12 दिन की यात्राएं बुक कर रहे हैं। बच्चे, माता-पिता और दादा-दादी — सभी मिलकर त्योहार को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं।"

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप के गंतव्य जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन और पुर्तगाल इस बार सबसे पसंदीदा बने हैं। वहीं, एशिया में वियतनाम, ओमान, मालदीव, बाली और कंबोडिया के लिए बुकिंग में भी भारी इजाफा हुआ है।

राजीव काले ने बताया कि वीजा-मुक्त या आसान वीजा वाले देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, दुबई, अबू धाबी, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पर्यटकों की मांग लगातार बढ़ रही है। घरेलू स्तर पर यात्री केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, अंडमान, चार धाम, कैलाश मानसरोवर, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थस्थलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ट्रैवल एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में "फेस्टिव ट्रैवल" भारत में एक नया उद्योग बनकर उभरेगा, जिसमें लोग अपने त्योहारों को घर के बजाय आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में मनाना पसंद करेंगे — जहां दीपावली की रोशनी आस्था और आनंद दोनों का प्रतीक बन जाएगी।